

श्री लाल कृष्ण आडवाणी
लोकसभा में विपक्ष के नेता
का

इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के परिसंघ (फिक्की) की 80वीं वार्षिक सामान्य सभा के विशेष सत्र में भाषण

नई दिल्ली – 15 फरवरी, 2008

फिक्की के अध्यक्ष श्री हबील खोरकीवाला, निर्वाचित अध्यक्ष श्री राजीव चन्द्रशेखर, भारतीय व्यापार एवं उद्योग जगत के मुखियागण, सम्मानित अतिथिगण, देवियों एवं सज्जनों,

मुझे फिक्की की वार्षिक सामान्य सभा में एक बार फिर आकर बहुत खुशी हो रही है।

मैंने फिक्की के मंच से कई अवसरों पर भाषण दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी भी अनेक वर्षों तक आपसे जुड़े रहे हैं। वास्तव में, आपके भी अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से सम्बंध रहे हैं। यह आपको विचार करना है कि अन्य दलों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की सोच और व्यवहार कैसा रहा है?

कुल मिलाकर, मैं यह दावा कर सकता हूँ कि हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने लगातार निजी उद्यमों का समर्थन करने की नीति अपनाई है और उन वर्षों के दौरान भी लाइसेंस-कोटा-नियंत्रण राज के विरुद्ध अपना विरोध व्यक्त किया जब आर्थिक सुधारों पर कोई बहस नहीं होती थी। वास्तव में, सरकारी नियंत्रण का सोवियत मॉडल उस समय प्रमुख राजनीतिक फैशन और बौद्धिक सम्मोह था।

इसीलिए, हमने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी वी नरसिंह राव और उनके वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह का उस समय बेझिझक समर्थन किया जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी की अपनी पहली आर्थिक नीतियों को उलटने का साहस दिखाया। और जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने छह वर्षों तक स्थायी और सफल सरकार का संचालन किया तो हमने आर्थिक सुधारों के एजेंडा को तेज और व्यापक करने की कोशिश की जिसका परिणाम आप सभी ने देख ही लिया है।

मेरी पार्टी का सतत उद्यम-अनुकूल आर्थिक दर्शन

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी राजनीतिक और आर्थिक नीति की जड़ें विदेशी धरती में नहीं जमीं हुई हैं बल्कि इसकी जड़ें भारत की अपनी ही जमीन में गड़ी हैं और ये सदियों पुरानी परम्पराओं से पोषित हैं। हम किसी मत वाम और दक्षिण पंथ से बंधे हुए नहीं हैं। हम अन्य समाजों के ज्ञान और अनुभव से सीखने को तैयार हैं लेकिन हम हमेशा अपने राष्ट्रीय आदर्शों और सिद्धांतों को अपनाते रहेंगे और वस्तुतः, भारत की सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को समझते रहेंगे।

इसलिए, हमारा हमेशा यह विश्वास रहा है कि राजा के धर्म अथवा लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार के धर्म को, जहां कहीं भी समुदाय का धर्म व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और कृषि में शामिल है, धन जुटाने, फायदेमंद रोजगार पैदा करने और समाज की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए निभाना होगा। हिन्दी में एक कहावत है – **“राजा बने व्यापारी, प्रजा बने भिखारी”**।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की विशेष परिस्थिति और विदेशी शासन के अधीन उद्योगविहीन पिछली सदियों को देखते हुए राष्ट्र को बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने और सभी जनोपयोगी सेवाएं चलाने की जरूरत पड़ी। आज भी, राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि वह चुनिंदा स्ट्रेटजिक उद्योगों में शामिल रहे और सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की व्यवस्था को सुनिश्चित करे।

लेकिन, साठ के दशक और उसके बाद से जो हमने देखा कि राज्य का नियंत्रण धर्म-सिद्धांत बन गया, लालफीताशाही हावी हो गई और उद्यमशीलता में बदलाव आ गया। इससे राजनीतिक और नौकरशाही में भ्रष्टाचार की संस्कृति पनप गई और इसके परिणामस्वरूप, भारत की अर्थ-व्यवस्था को बुरी तरह से आघात पहुंचा।

हमारी सड़कें तंग और सीमित रह गईं। हमारे बंदरगाह छोटे रह गये। बड़े शहरों में भी हमारे हवाई अड्डे पुराने ढर्रे पर चलते रहे। हमने अपने रेलवे नेटवर्क का पर्याप्त रूप से न तो विस्तार किया और न ही उनका आधुनिकीकरण किया। हमने अपनी बढ़ती हुई आबादी की जरूरतों को पूरा करने और कृषि तथा उद्योगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बिजली और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए कदम नहीं उठाये। हमने अपने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सुधार नहीं किया ताकि बच्चों को गुणवत्तावाली उच्च शिक्षा दी जा सके और सुशिक्षित भारतीय लोगों को भारत में ही रोजगार पाने के अवसर पैदा किए जा सकें। हमारी प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुईं। इसके फलस्वरूप, भारत आज भी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास इन्डेक्स में काफी निचले स्तर पर है।

इन सभी बातों का प्रतिकूल प्रभाव न केवल आर्थिक क्षेत्र में ही है बल्कि स्वाभाविक तौर पर **मनोवैज्ञानिक भी है**। लाखों युवाओं, महत्वाकांक्षी और मेधावी भारतीयों को यह यकीन होने लगा कि वे अपने सपनों को केवल विदेश जाकर ही पूरा कर सकते हैं। यह भी एक गलत धारणा बन गई कि कोई भी गुणवत्तापरक और आधुनिक वस्तु विदेश में ही मिल सकती है। इसलिए आयातित वस्तुओं की चाह पैदा हो गई और भारतीय वस्तुओं को घटिया समझने की प्रवृत्ति पैदा हो गई।

- कोई भी राष्ट्र कमजोर आत्म-विश्वास के साथ मजबूत नहीं बन सकता।
- कोई भी राष्ट्र छोटी महत्वाकांक्षा और छोटी-छोटी उपलब्धियों से महान नहीं बन सकता।
- कोई भी राष्ट्र अपने बहुत बड़े मानव संसाधन को गरीब रखकर धनवान नहीं बन सकता।

भारत उच्च-उपलब्धि की राह पर

यह खुशी की बात है कि अब काफी कुछ बदलाव आ रहा है। इसका श्रेय 1990 के दशक के आरम्भ में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों को जाता है। तथापि, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि भारत के विकास में कुछ व्यर्थ गए दशकों की वजह से काफी हद तक बाधा पड़ी।

मुझे इस बात की विशेषकर खुशी है कि श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारी अपनी सरकार ने भारत को आगे ले जाने में काफी योगदान दिया।

उदाहरण के लिए, **राजमार्ग विकास परियोजना** से न केवल हमारी सड़कों का विस्तार हुआ बल्कि हमारी सोचने की प्रक्रिया का भी विस्तार हुआ। आम लोगों ने भी यह स्वीकार किया कि भारत ऊंचा सोच सकता है, रिकार्ड समय में परियोजनाओं को लागू कर सकता है और जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, उन्हें हासिल कर सकता है।

इसी तरह, **मई 1998 में पोखरण में किए गये परमाणु परीक्षण** का राष्ट्रीय सुरक्षा की परिधि से भी काफी आगे प्रभाव पड़ा। महाशक्तियों के विरोध के बावजूद उठाये गये इस साहसिक कदम ने भारतीयों को गौरवान्वित किया और आत्मविश्वासी बनाया। और यदि हम भारत-अमेरिकी परमाणु करार का विरोध कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि 1998 में भारत द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को

निष्क्रिय कर दिया जाए। हम अपनी विदेश नीति के ढांचे के तहत, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की भावी सरकार भारत की सभी रणनीतिक साझेदारियों को महत्व देगी और यह न तो किसी को क्षति पहुंचायेगी और न ही दूसरे पर प्रभाव डालेगी।

अब भारतीय उद्योगपति अनेक उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। वे देश के भीतर नई आर्थिक नीतियों का इस्तेमाल करते हुए विश्व अर्थ-व्यवस्था में उभरते हुए अवसरों का भी लाभ उठा रहे हैं। वे सफलता की ऐसी कहानियां लिख रहे हैं जिनकी एक शताब्दी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मैं इन उपलब्धियों के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ जिनकी वजह से भारत के बारे में विश्व परिदृश्य में, लोगों की सोच में बदलाव आया है बल्कि उनके बारे में तथा उनके देश के बारे में भारतीय लोगों की सोच में भी बदलाव आया है।

और, जब मैं भारतीय उद्योगपतियों की सराहना करता हूँ तो मैं न केवल उन उद्योग समूहों के मालिकों की ही प्रशंसा कर रहा हूँ जिनके बारे में हर कोई जानता है, इसमें कोई शक नहीं है, वे सराहना करने के योग्य हैं। बल्कि मैं लाखों कामगारों, प्रबंधकों, इंजीनियरों, आर. एंड डी कार्मिकों और इन उद्यमों में कार्यरत अन्य लोगों की भी सराहना कर रहा हूँ।

- इसलिए, जब मैं नेनो, जो टाटा घराने द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे सस्ती कार है, के बारे में सोचता हूँ तो मैं न केवल रतन टाटा की हिम्मत और इरादे की सराहना करता हूँ बल्कि मैं उस पूरी टीम को भी साधुवाद देता हूँ जिसने इसे चुनौती के रूप में लिया और सफलता हासिल की। **हम उत्पादन के क्षेत्र में ऐसे बहुत से भारतीयों की सफलताओं को प्रोत्साहित करेंगे।**
- मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है जब मैं दिल्ली, मुंबई बंगलौर और दूसरी जगहों पर बड़े और बेहतर हवाई अड्डों पर निर्माणकार्य होते हुए देखता हूँ। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि **देश का प्रत्येक हवाई अड्डा आधुनिक बने और देश के हर हिस्से को हवाई सम्पर्क से बेहतर ढंग से जोड़ा जाए।**
- मुझे प्रसन्नता होती है कि हम दिल्ली में विश्वस्तरीय मेट्रो प्रणाली बना रहे हैं। **हम ऐसे सैकड़ों श्रीधरनों को सशक्त बनाएंगे – और हम ऐसे योग्य अधिकारियों को हमारी व्यवस्था में लेंगे – जिससे हम सुरक्षा और आम यात्री की सुविधा पर विशेष ध्यान रखते हुए अपनी रेलवे प्रणाली का कम समय में आधुनिकीकरण कर सकें।**
- मुझे यह जानकर खुशी होती है कि भारत काल सेंटर, दुनिया के बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिंग का केन्द्र और दुनिया के नॉलेज प्रोसेस आउट सोर्सिंग-के रूप में तेजी से उभर रहा है। यह सब भारत में टेलिकॉम और आई टी क्रांति के चलते सम्भव हो सका, कहा भी जाता है कि "न्यूयार्क में हड्डी तोड़ो, चेन्नई में एक्स-रे देखो।" **यह मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है कि उपेक्षित वर्गों के हमारे लाखों प्रतिभाशाली युवक और युवतियां अच्छी शिक्षा किस तरह प्राप्त करें ताकि वे भी इन व्यवसायों में प्रवेश पाकर लाभान्वित हो सकें।**

मैंने सिर्फ चार उदाहरणों का उल्लेख किया है लेकिन ऐसे और बहुत से उदाहरण हमारे आस-पास देखने को मिलते हैं, जिनसे यही सिद्ध होता है कि **भारत अब एक बड़ी ऊंचा छलांग लगाने के कगार पर पहुंच गया है।**

हमें भारत के विकास का दीर्घकालिक विज़न विकसित करना चाहिए।

मित्रो, विगत के व्यर्थ गए दशकों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर सोचें कि हाल की हमारी ये उपलब्धियां हमें क्या संदेश देती हैं? मेरे अनुसार, ये बताती हैं कि यह भारतीय राजनीतिक, आर्थिक और बुद्धिजीवी नेतृत्व का दायित्व है कि वे आने वाले अनेक दशकों की ओर देखें। तेजी से बदलते विश्व में, हमें

जरूरत है भारत की आवश्यकताओं की अच्छी समझ, चुनौतियों ओर अवसरों को भविष्य की रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझने की, विशेष रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक वर्ग की सिर्फ शासन काल की अवधि या अगले चुनावों तक सोचने की प्रवृत्ति भारत का भला नहीं कर सकती।

मैं व्यवसायी समुदाय से आग्रह करता हूँ कि वे अपने लिए और राष्ट्र के लिए एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य विकसित करें।

हम कहते हैं कि हम सन् 2020 तक अपने को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे हम कहते हैं कि हम 21 वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाना चाहते हैं। हम कैसे इन नारों को यथार्थ में बदल सकते हैं जब तक हमारे पास दीर्घकालिक विज्ञान, एक व्यापक दृढ़ राष्ट्रीय इच्छा और राष्ट्रीय उद्दाम क्षमता नहीं हो, जो इस विज्ञान को सच्चाई में बदल सके।

आप में से कुछ लोग इस पर आश्चर्य कर रहे होंगे कि मैं भविष्य की बात क्यों कर रहा हूँ और लोकसभा में विपक्ष का नेता होते हुए भी वर्तमान सरकार के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। यूपीए सरकार के बारे में मुझे जो कहना होगा वह मैं दस दिन बाद शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में कहूँगा। जिस ढंग से यह सरकार चल रही है या काम नहीं कर रही है और आंतरिक रूप से पंगु है— इन सब बातों तथा इसके अतीत या वर्तमान के बारे में कहने की वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। ?

लोग पहले से ही यूपीए सरकार से आगे की ओर देखने लगे हैं। इसलिए, मैं आपको आश्चस्त करता हूँ कि हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में भविष्य की तैयारियों में गम्भीरता से जुटे हैं।

लोग परिवर्तन के लिए आतुर हैं लेकिन वे सिर्फ सरकार में परिवर्तन नहीं चाहते कि कुछ पुराने चेहरों के स्थान पर नए चेहरे आ जाएं। जैसाकि मैं अपनी राजनीतिक सभाओं में कहता रहा हूँ कि लोग शासन की संस्कृति और कार्यकुशलता में परिवर्तन देखना चाहते हैं। वे, सरकारी कामकाज में सभी स्तरों पर परिवर्तन देखना चाहते हैं।

मैं मानता हूँ कि एक व्यवसायी होने के नाते आप भी अपनी समस्याओं और जरूरतों के निपटारे के लिए सरकारी मशीनरी में परिवर्तन की चाह रखते होंगे। मैं जानता हूँ कि लघु एवं मझोले क्षेत्र के उद्योगपति और उससे भी छोटे क्षेत्रों—जो अभी भी बहुत छोटे क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्र में लाखों उद्यमी और श्रमिक लगे हैं— एक ऐसा सरकारी माहौल चाहते हैं जो उनके लिए सहायक हो न कि उनको परेशान करनेवाला हो। **कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या आर्थिक सुधारों ने छोटे भारतीय – छोटे किसान, छोटे दस्तकार, शहरों और गांवों में छोटी-छोटी सेवाएं प्रदान करने वालों के लिए क्या कुछ परिवर्तन किया है।**

ये वर्ग भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा और वस्तुतः कार्यबल है।

सुधारों के बाद की भारत की समृद्धि सम्बंधी आंकड़े बताते हैं कि हमारे समाज में असमानता बढ़ी है। असंगठित क्षेत्र में उद्योगों सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग (NCEUS) की एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 8 करोड़ 60 लाख भारतीय 20 रूपए प्रतिदिन कमाते हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री विमल जालान का एक वक्तव्य मुझे देखने को मिला जिसमें कहा गया है कि 20 सर्वाधिक अमीर भारतीय हमारे देश में 30 करोड़ गरीबों के बराबर कमाते हैं।

इस वास्तविकता को हम कैसे सहन कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कदापि इसे नहीं सहन करेंगे। हम ऐसे साहसी और आधुनिक तरीके अपनाएंगे जो पूरे देश के सभी भागों और सामाजिक वर्गों में सम्पदा वितरण को सुनिश्चित कर सकें।

वस्तुतः मैं स्वयं व्यवसायी समुदाय से—और मीडिया से भी— आग्रह करता हूँ कि वे भी सोचें कि हम वर्तमान वृद्धि को कैसे अधिक समान तथा ठोस बना सकते हैं। मैं इस सम्बन्ध में आपके सुझाव आमंत्रित करता हूँ।

धन बढ़ाने के मुद्दे पर, मैं अवश्य ही अपनी चिंता मुखरित करना चाहूंगा और ऐसा करते समय मैं अपने देश के लाखों लोगों की चिंता में सहभागी होना चाहता हूँ और यह चिंता है—स्टॉक मार्केट में अस्थिरता को लेकर। जहां तक यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली में होने वाले घटनाक्रमों का परिणाम है, तो यह समझा जा सकता है। लेकिन पूंजी बाजार में किसी भी खिलाड़ी द्वारा छल—कपट, कदाचार और सिस्टम के दुरुपयोग का कोई स्थान नहीं हो सकता। **अपराधियों को सख्ती से दण्डित करना चाहिए।**

जीडीपी को इस ढंग से पुर्नभाषित करना

जिससे आम आदमी लाभान्वित तथा उत्साहित हो सके

इसलिए जब मैं भारत में किसी भी सरकार के सम्मुख भविष्य की चुनौतियों के बारे में सोचता हूँ तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा काम है छोटे से छोटे भारतीय को भारत की प्रगति में एक लाभार्थी बनाना और उत्साही सहभागी बनाना।

अपने दल और एनडीए की तरफ से मैं कह सकता हूँ कि हमने देश और आम आदमी की जरूरतों के समाधान के लिए पांच वर्ष के लघुकालिक और आनेवाले दशकों वाले दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में तीन मानक तय किए हैं।

और ये तीन मानक हैं सुशासन, विकास और सुरक्षा।

और जब मैं "सुरक्षा" का उल्लेख करता हूँ तो मेरा तात्पर्य राष्ट्रीय सुरक्षा के सिर्फ बाह्य और आंतरिक पहलुओं से जुड़ा नहीं है। वो तो है ही और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। जिसके कारण हम राजनीतिक वर्ग के अन्यो की तुलना में आतंकवाद के विरुद्ध अधिक शक्ति के साथ और सतत् रूप से अभियान चला रहे हैं।

लेकिन सुरक्षा से मेरा मतलब मानव सुरक्षा भी है। आम आदमी, विशेषकर किसानों जिनमें से अनेकों को कर्ज और भूखमरी के चलते आत्महत्याएं करनी पड़ीं। **आर्थिक सुरक्षा और आजीविका की सुरक्षा।**

सुरक्षा से मेरा अभिप्राय प्रत्येक भारतीय की **शैक्षणिक सुरक्षा** और **स्वास्थ्य सुरक्षा** से भी है।

इस प्रकार का समन्वित विकास और समग्र सुरक्षा आर्थिक वृद्धि के विकास के ऐसे मॉडल से हासिल नहीं किया जा सकता जो कुछ कोई लाभ पहुंचाए और बहुतों को कंगाल बनाए।

इसलिए ही जीडीपी की 8 प्रतिशत या 9 प्रतिशत वृद्धि दर यद्यपि महत्वपूर्ण है, मगर फिर भी यह मुझे अपील नहीं करती और न ही करोड़ों आम भारतीयों को।

यदि कोई मुझे पूछे कि **"आप किस तरह की जीडीपी वृद्धि चाहते हैं?"** तो मैं कहूंगा इस तरह कि :

- **"जी" से गुड गवर्नेन्स यानि सुशासन** – राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तर के सभी स्तरों पर
- **"डी" से डेवलपमेंट यानी विकास** – सभी क्षेत्रों तथा सभी भारतीयों के लिए और
- **"पी" से प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा** – सभी नागरिकों के लिए।

जीडीपी के प्रति यह दृष्टि करोड़ों साधारण भारतीयों की उद्यमशीलता और सृजनात्मक ऊर्जा को उन्मुक्त करेगी। यह हासिल करने के लिए अनिवार्य रूप से लम्बा समय लगेगा। लेकिन इसे हासिल करना हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

राजनीति और सुशासन को एक नई दिशा

मित्रो, पिछले एक दशक से ज्यादा मैं इन तीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता प्रकट करता आ रहा हूँ। वास्तव में, मेरी सर्वाधिक लम्बी यात्रा – दो महीने लम्बी स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, जो भारतीय स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 1997 में हुई थी, का मुख्य मुद्दा था **स्वराज को सु-राज**

में बदलना। इस आदर्श को प्रोत्साहित करने की जितनी कोशिश एनडीए के 6 वर्ष के शासन काल में हम कर सकते थे, हमने की।

मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इन सिद्धांतों में मेरा विश्वास उस समय और ज्यादा मजबूत हुआ जब गुजरात के हाल ही के चुनावों में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मेरी पार्टी को शानदार सफलता प्राप्त हुई। इसने दूरगामी महत्व का संदेश दिया है।

हम सभी को इस पर गर्व है कि 1947 के बाद से भारत एक जीवंत और उर्जात्मक लोकतंत्र के रूप में उभरा है। हालांकि विगत साठ वर्षों के भारतीय राजनीति के घटनाक्रम का एक प्रेक्षक होने और इसमें भागीदार रहने के चलते, इसमें आई एक मुख्य कमी को मैंने पाया है। अधिकांश राजनीतिक दल मानने लगे हैं कि वोट बैंक की राजनीति ही चुनाव जीतने और सत्ता पाने का एक सुनिश्चित रास्ता है। उनके मन में यह धारणा भी घर कर गई है कि सुशासन, लोकतंत्र और सार्वजनिक जीवन में शुचिता ऐसी प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जो वोट दिला सकें।

इस पृष्ठभूमि में, 2007 में गुजरात चुनावों में श्री मोदी की जीत वोट बैंक की राजनीति पर सुशासन, विकास और सुरक्षा की विजय का संकेत देती हैं। भले ही देर से क्यों न हो, यह भारत के लिए स्वागत योग्य है।

यदि मेरी पार्टी और एनडीए, आगामी संसदीय चुनावों में लोगों का जनादेश जीतती है तो सुशासन, विकास और सुरक्षा जैसी तीनों प्रतिबद्धताएं हमारे समान न्यूनतम कार्यक्रम का मार्गदर्शक सिद्धान्त होंगी।

अगले महीने में हमने सभी नौ एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय किया है। यह भी हमारे गठबंधन हेतु समान मार्ग दर्शक सिद्धांत गढ़ने की दिशा में एक कदम है।

संक्षेप में कहूँ तो एनडीए के हम लोगों ने केन्द्र और प्रदेशों में शासन का अच्छा अनुभव प्राप्त किया है। इन अनुभवों और अच्छे विचारों का उपयोग करते हुए तथा सभी ओर से मिल रहे सुझावों और समाज के सभी वर्गों से समर्थन मांगने के साथ हम राष्ट्र के सामने एक महत्वाकांक्षी और प्रेरक एजेण्डा प्रस्तुत करेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं, हमारे काम में आपके विचारों और समर्थन का सम्मान करता हूँ।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और फिक्की को धन्यवाद देता हूँ कि उसने आपके साथ बातचीत करने का मुझे अवसर प्रदान किया।

धन्यवाद